reservation. For scientific posts we do not have any special reservation.

श्री पां० ना० राजभोज : गजेटेड पोस्ट के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार जब तक नहीं मिलते तब तक क्या वह जगह भरने के लिए यू० पी० एस० सी० को अधिकार है या नहीं ?

श्री हुमायूं कबिर : शायद आनरेबिल मेम्बर को मैं साफ नहीं बतला सका। जो आरडिनरी गजेटेड पोस्ट हैं उन में शिड्यूल्ड कास्ट के लिए कुछ रिजर्वेशन है लेकिन साइन्टिफिक पोस्टों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ।

SHRI SATYACHARAN: It is not quite clear from the statement of the hon. Minister as to why the Scheduled Caste candidates could not be appointed in the category of Class IV posts. It is here admitted very clearly by the representative of the Ministry as follows:

> "The representative of the Ministry, however, undertook to look into the question as to why none of the scheduled caste applicants for Class IV posts in the Central Road Research Institute and Central Food Technological Research Institute during 1958-59 and 1959-60 respectively was appointed."

SHRI HUMAYUN KABIR: I am not responsible for 1958-59, I am certainly for today, and I say that on the 1st March 1961 there were these people in position. If the hon. Member's quarrel is that in 1956 there were none and these 33 have been appointed in one and 22 in another since then, then he should congratulate the laboratories and not criticize.

बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर नियंत्रण का खाद्यान्नों के भावों पर प्रभाव

***१३१. श्री राम सहाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों पर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण से खाद्यानों के भावों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका पता लगाने के लिए क्या कोई जांच की गई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस ऋण पर नियंत्रण से खाद्यान्न व्यापारियों को अधिक ब्याज पर रुपया लेना पड़ता है और किसान को अपनी पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिल पाती ?

t [EFFECT OF BANK CREDIT CONTROL ON FOODGRAIN PRICES

*131. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to-state:

(a) whether any enquiry has been made to find out the effect of bank, credit control against foodgrains on prices of foodgrains; and

(b) whether it is a lact tnat due to the control on this credit foodgrain traders are forced to take credit on high rate of interest and farmers do> not receive full price for their produce?]

वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक में, इस बात की बराबर जांच की जाती है कि अनाज की कीमतों पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के नियंत्रण का क्या प्रभाव पड़ता है।

(ख) जब तक वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी क्षेत्र से बाहर असंगठित मुद्रा बाजार (मनी मार्केट) मौजूद है, तब तक अनाज के व्यापारी ब्याज की जिन दरों पर वहां से ऋण मिलता रहेगा, लेते रहेंगे। फिर भी, यह मानने का कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता कि किसानों को अपनी उपज का जो मूल्य मिलता है वह इस बात से बहुत कम हो गया है ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF FINANCE (SHRI B. R. BHAGAT): (a) The effect of bank credit control on the

†[ ] English translation.

prices of foodgrains is under continual examination at the Reserve Bank of India.

(b) So long as there is an unorganised money market outside the commercial banks and the co-operative sector foodgrain traders will continue to obtain credit from it at available rates of interest. There is no *prima facie* reason, however, to believe that this fact has severely depressed the price which farmers receive for their produce.]

श्री राम सहाय : मेरा प्रश्न यह था और मेरे प्रश्न पूछने की गरज यह थी कि जब मंडियों में गल्ले की खरीदारी होती है, जब किसान का गल्ला खरीदा जाता है तो उस समय बैंक की तरफ से रुपया न मिलने के कारण और वैगनों की सप्लाई न होने की वजह से व्यापारियों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि गल्ला खरीद सकें। इसका नतीजा यह होता है कि गवर्नमेंट द्वारा जो अनाज के दाम निश्चित किये जाते हैं उस से कम भाव में किसानों का अनाज खरीदा जाता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि क्या उस जमाने में जब कि किसान के गल्ले की खरीदारी व्यापारियों द्वारा होती है, उस समय बैंकों के रूल्स कुछ रिलेक्स किये जा सकते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मैंने जैसा बतलाया कि रिज़र्व बैंक इस बात पर हमेशा विचार और जांच-पड़ताल करता रहता है। और उस के पास विभिन्न मंडियों के आंकड़े आते हैं कि रुपये की कितनी जरूरत है। इन मंडियों में खरीद और बिक्री के लिए जितने रुपयों की जरूरत होती है उसी हिसाब से वह सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पालिसी लागू करता है। अगर रुपये की जरूरत हुई तो वह उसका बन्दोबस्त करता है और अगर चीजों के दाम बढ़ते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। रिज़र्व बैंक सब चीज के बारे में विस्तार से जांच पड़ताल करता है और तब अपनी पालिसी निर्धारित करता है।

श्री राम सहाय : मेरा निवेदन यह है कि क्या इस बारे में शासन द्वारा मौके पर जांच करने का ख्याल है जिस से सरकार को मालूम हो सके कि दरअसल मंडियों में बैंकों की रेस्ट्रिक्शन की वजह से गल्ले की खरीदारी नहीं हो रही है।

श्री बी० आर० भगत : रिज़र्व बैंक शासन का एक बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग है।

SHRIMATI SAVITRY DEVI NIGAM: May I know if these measures of credit control which have been taken, have been responsible , for discouraging hoarding and for stopping fluctuations in prices?

SHRI B. R. BHAGAT: That is the objective and to a great extent these measures have been successful in achieving that objective.

SHRI A. D. MANI: Is it a fact that in recent months there has been a slackening of deposits and this has led to the tightening of the credit control?

SHRI B. R. BHAGAT: It is true that over a period the deposits in banks were going down, although in recent months, that is to say, in the last fortnight or so, the deposits have been up.

PROJECTS BASED ON ASSAM NATURAL GAS

*132. SHRIMATI SAVITRY DEVI NIGAM: Will the Minister of STEEL, MINES AND FUEL be pleased to refer to page 6 of the summary of the Department of Mines and Fuel for 1960-61 and state:

(a) the names of the places where the project based on Assam natural gas are going to be established; and

(b) how much money is needed to establish polyethylene, cis-4-poly-butadiene factory and what are the future prospects of annual production?